



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 016/2023-बीएचओ/281  
प्रति,

दिनांक : 25/01/2024

प्रधान सचिव (वन)  
मध्यप्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीव-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु 176.24 हेक्टेयर (34.32 हे. सीधी वनमण्डल एवं 141.92 हे. सिंगरौली वनमण्डल) आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत ।

- संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1230/2022/10-11/5183 दिनांक 03/12/2023.  
2. आर्.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/277 दिनांक 24/01/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर्.ई.सी. बैठक दिनांक 10/01/2024 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 24/01/2024 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. Construction of underground components(Tunnels) and over ground components is proposed in the proposal, hence the State Government should submit the following documents/information:
  - i. Land schedule showing length, width and area wise details of all components in surface area and in underground area.
  - ii. Enumeration for surface area and underground area in separate sheet because in general the trees of underground area are not required to be felled. Therefore, it needs to be clarified as to how many actual number of trees need to be felled.
  - iii. The calculation of NPV and CA may also need to be proposed/calculated as per the prevailing rules/guidelines for underground and overground area requirement.
2. The proposal includes both forest and non-forest areas, so the State Government should make a complete KML in which all the components proposed in forest and non-forest areas should be clearly shown in different colors.
3. The cost benefit analysis in prescribed format shall be submitted.
4. The Rehabilitation plan shall be submitted

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।